प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक

संस्थापक स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

मालव समाचार

इंदौर | वर्ष : 61 ■ अंक 08 ■ 28 फरवरी 2025 ■ पृष्ठ-12 ■ मूल्य - 3.00 प्रकाशन के 6 दशक

मध्यप्रदेश में निवेश का बूम

30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 21.50 लाख लोगों को जॉब

मध्यप्रदेश 2047 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए तैयारः सीआईआई रिपोर्ट पेज- 03

मोदी का जलवा.... राहुल फिर जीरो पर बोल्ड

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की बढ़त वापस छीनी; 5 राज्यों में कांग्रेस सिर्फ 23% सीटें जीत सकी

जीरो- जीरो- जीरो! ये 2015, 2020 और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली सीटों की संख्या है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 52 से बढ़ाकर 99 पर पहुंची थी। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। मोमेंटम कांग्रेस के फेवर में दिख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये मोमेंटम वापस छीन लिया है।

लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से मोमेंटम **वापस कैसे छीना?**

विशेष रिपोर्ट पेज-6-7-8

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को अनेक रेखाओं को पार करना होगा, उनके लिए क्या है सबसे बड़ी चुनौती ?

दिल्ली कैबिनेट की पहली मीटिंग में अहम फैसलों पर लगी मुहर, आयुष्मान योजना को मंजूरी मिली

पेज- 9

नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की आंधी में उड़ा पंजा

छत्तीसगढ़

10 नगर निगम, 35 नगर पालिका और 81 नगर पंचायत पर भाजपा का कब्जा

निकाय-चुनाव में बीजेपी की जीत की 5 बड़ी वजह

पेज- 10

मोदी-शाह नए चेहरों को ही सीएम क्यों बनाते हैं?

पेज- 05

सीएम डॉ. मोहन यादव का बढ़ा कद

पीएम मोदी भी कामकाज से खुश

योगी, फणनवीस और हेमंता की कतार में पहुंचे डॉ. यादव

पेज- 02

तेजस्वी के लिए मुसीबत बने लालू!

बिहार

'भूरा बाल' से 'फालतू कुंभ' तक... तेजस्वी को लालू यादव के किन बयानों से जूझना होगा, पिता की बदौलत यहाँ तक आये, आगे नुकसान या फायदा ?

पेज- 11

जरा ये धूप ढल जाए तो हाल पूछेंगे,
यहां कुछ साये अपने आप को खुदा बताते हैं।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
28 फरवरी 2025

सीएम डां मोहन यादव का बढ़ा कद

पीएम मोदी भी कामकाज से खुश

योगी, फणनवीस और हेमंता की कतार में पहुंचे डॉ. यादव

भोपाल। भाजपा में इन दिनों नीचे से लेकर ऊपर तक पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। यह परिवर्तन सत्ता के साथ ही संगठन तक में हो रहा है। यही वजह है कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारों में कमान दूसरे पंक्ति के नेताओं के हाथों में सौंपी जा चुकी है। इस परिवर्तन का साक्षी मप्र भी है। यहां पर भी करीब एक साल पहले जब सरकार बनी तो राजनैतिक प्रेक्षकों के अनुमानों को ध्वस्त करते हुए डां मोहन यादव जैसे विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई थी। माना जा रहा था कि वे शिवराज सिंह चौहान जैसे राजनैतिक विशाल कद के नेता के सामने खुद को कैसे साबित करेंगे। अब इस तरह के सवाल उठना बंद हो गए हैं। इसकी वजह है उनकी कार्यशैली और अथक परिश्रम। यही वजह है कि अब उनकी गिनती उन नेताओं में होने लगी है जिसमें योगी आदित्यनाथ, देवेन्द्र फणनवीस और हेंमता विश्वशर्मा की गिनती होती है। यह वे नेता हैं, जिनकी पहचान अब राज्य से बाहर देशभर में हो चुकी है। इनमें ही अब डां मोहन यादव भी शुमार हो चुके हैं। यही वजह है कि ग्लोबल इंन्वेस्टर समिट में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब बीते रोज पार्टी के नेताओं से करीब ढाई घंटे तक बातचीत की तो सरकार के कामकाज को लेकर कोई प्रश्न नहीं पूंछा। इस दौरान उनके द्वारा तमाम सवाल जबाब किए गए। इस दौरान बैठक में पार्टी के सांसद विधायकों से लेकर संगठन के पदाधिकारी तक शामिल थे। इससे साफ संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी डॉ. मोहन यादव के कामकाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

प्रधानमंत्री करीब दो दशक तक संघ के प्रचारक और इतने ही वर्षों तक भाजपा में संगठन मंत्री रहे हैं। जबकि पिछले 24 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर कामकाज करते आ रहे हैं। इसकी वजह से वे जल्द ही सामने वाले का परख लेते हैं। पार्टी को डॉ मोहन यादव से बहुत उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री समिट की तैयारियों और उसके आयोजन की भव्यता से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने भावी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए भी फीडबैक लिया लिया है। अमित शाह भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल,ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चुनावी रणनीति और क्षेत्र के विकास के लिए अहम टिप्स दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशाभाऊ ठाकरे कंवेंशन सेंटर में प्रदेश के मंत्रियों, भाजपा विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर उन्हें कुछ गुर भी बताए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विधायकों से यह भी पूछा कि वे अपने क्षेत्रों में विकास के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में विधायकों ने अपने काम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और नेताओं से कहा कि अपने क्षेत्रों में विकास के लिए योजना बनाएं और कार्यों की मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच रहकर काम करें और विकास कार्यों को जमीन पर लाकर उन्हें महसूस कराएं।

मोदी ने विधायकों से कई सवाल किए, जिसका कुछ विधायकों ने जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री ने विधायकों को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया। उनका मानना था कि जब एक विधायक अपना व्यक्तित्व सुधारता है तो वह क्षेत्र में अच्छे काम कर सकता है और इससे चुनावी जीत में भी मदद मिलती है। पीएम ने विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लेने की सलाह दी। इससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विधायक जब पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में जाते हैं और अधिकारियों से संवाद करते हैं, तो इससे क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता मिलती है। बैठक के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बैठक में विधायकों से यह भी कहा कि वे अपने कामकाज और व्यवहार में में घमंड से दूर रहें, व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें और क्षेत्र के विकास के लिए नवाचार करें। साथ ही, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें और अपनी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएं।

जब बैठक में छा गया सन्नाटा

मोदी ने पूछा... सोशल मीडिया पर किसके एक करोड़ फॉलोअर्स... नहीं मिला जवाब; एमपी के भाजपा विधायक-सांसदों को दिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के बीजेपी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों से सवाल पूछा, बताइए किस विधायक के सोशल मीडिया पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इस सवाल पर हॉल में चुप्पी छा गई, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के पूर्व राष्टीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से जुड़े संस्मरण पूछे तो एक दर्जन विधायकों ने अपने संस्मरण सुनाए।

यह दिए टिप्स

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं को व्यवहार में विनम्रता रखने, क्षेत्र के लगातार दौरे करने, प्लानिंग बनाकर काम करन की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा न हो कि भागदौड़ बहुत करते हों और रिजल्ट कुछ न निकले। उन्होंने इस दौरान अपनी सेहत का भी ध्यान रखने, सोशल मीडिया का सदुपयोग करने, अपने, सरकार और पार्टी के कामों को पब्लिक तक पहुंचाने , योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में शामिल होने और अपने क्षेत्र में नए नवाचार करें और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को दिखने का भी सुझाव दिया। पीएम मोदी ने विधायकों से कहा कि विधानसभा में वह तैयारी के साथ जाएं। विधायक जब पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं तो अधिकारी प्रभावित होते हैं। वह विधायक अपनी एक अलग पहचान बनाता है। इससे क्षेत्र में काम करवाना आसान होता है। क्षेत्र का विकास होता है तो चुनाव जीतने में भी आसानी होती है।

सफलताओं से सीएम मोहन यादव का ग्राफ बढ़ा...

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की छवि अब राष्ट्रीय नेता के रूप में बन रही है। पार्टी भी लगातार उनकी इमेज बिल्डिंग में लगी है। उन्हें देश के अलग-अलग चुनावी राज्यों में हाल के दिनों में प्रचार के लिए भेजा गया था। जब हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है कि डॉ. मोहन यादव अब बीजेपी में लंबी रेस के घोड़ा हैं।हरियाणा में विधायक दल की मीटिंग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम डॉ. मोहन यादव भी पहुंचे थे। वहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीएम डॉ. यादव कदमताल करते दिख रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि सीएम का कद कैसे भाजपा में बड़ा हो रहा है। साथ ही पार्टी भी उन्हें उभारने में लगी है। भाजपा की कोशिश है कि सीएम डॉ. मोहन यादव को पार्टी के अंदर यादवों के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, इसलिए हरियाणा में उन्हें बड़ी भूमिका दी गई। सीएम डॉ. यादव को यादवों के नेता स्थापित कर भाजपा यूपी-बिहार के यादवों को साधना चाहती है। सीएम बनने के बाद मोहन यादव सबसे पहले बिहार भी गए थे। वहां यादवों की 17 फीसदी आबादी है। 2025 में वहां विधानसभा के चुनाव हैं। यही स्थिति यूपी में भी है। पार्टी इन दोनों राज्यों में यह संदेश देने की कोशिश करेगी। हमने आपके समाज के जमीन से जुड़े नेता को यहां तक पहुंचाया है। सीएम बनने के बाद मोहन यादव की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100 फीसदी रहा है। पहली बार मध्यप्रदेश में भाजपा लोकसभा की 29 सीटें जीत गई। इसके बाद एक उपचुनाव हुआ, उसमें भी जीत मिली। साथ ही कमलनाथ के अभेद किले छिंदवाड़ा को ध्वस्त कर दिया। इससे साफ है कि वह केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। इन सफलताओं से सीएम मोहन यादव का ग्राफ बढ़ा है। ।

30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 21.50 लाख लोगों को जॉब

मध्यप्रदेश में निवेश का बूम

पूरा राज्य बनेगा मिनी मुंबई, दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर विकसित होगा इंदौर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल। भोपाल में दो दिन चली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश को 30 लाख 77 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। समिट में पहले दिन 24 फरवरी को 22 लाख 50 हजार 657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए थे।दूसरे दिन 25 फरवरी को 4 लाख 11 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 2 दिनों में 26.61 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनसे 17.34 लाख रोजगार की संभावना है। दो दिनों में 6 विभागीय समिट हुई हैं, जिनमें 500 से ज्यादा एनआरआई शामिल हुए और अपने निवेश प्रस्ताव रखे।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राज्य को मिनी मुंबई बनाने की प्लानिंग है। यह घोषणा भोपाल में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2025 के दौरान की गई। योजना के तहत, इंदौर को दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जबकि बाकी प्रदेश इंदौर जैसा बनेगा। इसके लिए मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, जिसमें कई जिलों को आपस में जोड़कर बड़े शहर बनाए जाएंगे।

एविएशन कंपनी फ्लाई भारती के साथ उज्जैन में एयरपोर्ट डेव्हलपमेंट के लिये एमओयू हुआ। इसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं, एअर इंडिया एक्सप्रेस और मध्यप्रदेश नागरिक विमानन विभाग के बीच 5 नई फ्लाइट के लिए एमओयू साइन हुआ है। समिट के दूसरे और आखिरी दिन समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इससे पहले प्रवासी मध्यप्रदेश समिट हुई। इसके बाद चार सेक्टर अर्बन, टूरिज्म, एमएसएमई और माइनिंग की समिट हुई। इस दौरान उद्योगपतियों ने एमओयू साइन किए।

दो दिवसीय ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दूसरे दिन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्ट-अप समिट सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी का अभिवादन करते हुए संबोधन में कहा कि यह दो दिवसीय समिट सकारात्मक भावना और योजनाबद्ध तरीके से आयोजित की गई है। संभागवार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर हमने प्रदेश में एक सकारात्मक औद्योगिक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। जिससे व्यापक संवाद हुआ है, और इसके उत्साहजनक परिणाम एमएसएमई क्षेत्र में देखने को मिले है। उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित किए बिना आर्थिक आधार मजबूत नहीं हो सकता। उद्योगों के विकास से ही रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और प्रदेश समृद्ध होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इससे नई संभावनाओं के द्वार खुले है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि समिट के अंत में जब आंकड़े आएंगे तब तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि एमएसएमई सेक्टर को अभूतपूर्व उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कमिटमेंट कर रही है और जिस पारदर्शिता के साथ नीतियों को लागू कर रही है, वह प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई विभाग की सराहना की और कहा कि सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सरकार और उद्यमी मिलकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे।

MP में अब तक 30.77 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान

समिट	निवेश के MOU	प्रस्तावित रोजगार
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव	2.34 लाख करोड़	2.74 लाख
इंटरेक्टिव सेशन	1.82 लाख करोड़	1.32 लाख
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025	26.61 लाख करोड़	17.34 लाख
कुल	**30.77 लाख करोड़**	**21.40 लाख**

25 सालों में बदल जाएंगे महानगर दिल्ली-मुंबई जैसा बनेगा इंदौर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में राज्य के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की। उन्होंने कहा कि इंदौर को दिल्ली-मुंबई जैसा और बाकी मध्य प्रदेश को इंदौर जैसा बनाया जाएगा। यह लक्ष्य मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इसमें पास-पास के जिलों को एक साथ जोड़कर बड़े शहर बनाए जाएंगे।उदाहरण के लिए, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और पीथमपुर (धार) को मिलाकर लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इसी तरह, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम के कुछ हिस्सों को भी एक साथ जोड़ा जाएगा। इस मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट में कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें सड़क, रेलवे, बिजली, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। इस योजना का लक्ष्य अगले 25 सालों में इन क्षेत्रों को महानगरों में बदलना है।

मध्यप्रदेश 2047 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार: सीआईआई रिपोर्ट

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था संभावित रूप से अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 2047-48 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (248.6 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ा सकती है, जो मौजूदा 164.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (13.6 लाख करोड़ रुपये) से 8.6% की सीएजीआर से बढ़ सकती है। 'एन विज़निंग मध्यप्रदेश इकोनॉमी 2047' शीर्षक वाली रिपोर्ट, आर्थिक विकास के लिए एक दृष्टिकोण, प्रमुख क्षेत्रों की पहचान, नीतिगत हस्तक्षेप और निवेश के अवसरों की रूपरेखा तैयार करती है जो राज्य के परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे।रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, सीआईआई के महानिदेशक, चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए समर्पित एक सक्रिय राज्य सरकार के साथ, मध्य प्रदेश 2047-48 तक भारत की जीडीपी में अपना योगदान मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर 6.0% करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

एआई पर सावधानी

पेरिस में संपन्न एआई एक्शन समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को स्वीकारते हुए सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया। फ्रांस के तत्वावधान में आयोजित समिट राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह-अध्यक्षता में संपन्न हुई। जो भारतीय प्रतिभाओं की वैश्विक साख को भी दर्शाता है। निश्चित रूप से यह समय एआई के क्षेत्र में भारत को अपनी प्राथमिकता तय करने का है। हालांकि, समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संवर्द्धन के रोडमैप पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गहरे मतभेद भी उजागर हुए। मेजबान फ्रांस, भारत व प्रमुख हितधारक चीन समेत दुनिया के साठ देशों ने डिजिटल विभाजन को कम करने के लिये एआई पहुंच को बढ़ावा देने, इसे खुला,समावेशी, पारदर्शी, नैतिक, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के संकल्प लेते हुए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने इस पर असहमति जतायी और हस्ताक्षर नहीं किए। ट्रंप जैसे तेवर अपनाते हए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने वैश्विक नेताओं व तकनीक उद्योग के अधिकारियों को चेताया कि अत्यधिक विनियमन से तेजी से बढ़ते एआई उद्योग की गति थम सकती है। जो बताता है कि अमेरिका एआई जोखिमों को कम करने के यूरोप के प्रयासों से खुश नहीं है। दरअसल, एक अधीर राष्ट्रपति के नेतृत्व में अमेरिका एआई की अपार संभावनाओं पर वर्चस्व चाहता है। उसे चीन की चुनौती भी स्वीकार नहीं है। हालांकि, इसी तर्ज पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई इस सदी में मानवता के लिये नया कोड लिख रही है। लेकिन साथ ही एआई को वैश्विक भलाई के लिये विकसित करने पर भी बल दिया। जिसका संदेश यह भी है कि इसका उपयोग देश विशेष अपने निजी हितों तक सीमित न रखे। यानी एआई नवाचार को बढ़ावा तो दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके नियमन को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, बड़े पैमाने पर एआई के दुरुपयोग की आशंका के बीच विश्वास, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये एक वैश्विक ढांचा स्थापित करना अपरिहार्य ही है।

दरअसल, यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने इस दिशा में सतर्क रुख अपनाया है ताकि जांच और संतुलन बनाने वाले कदमों से दुनिया में डीपफेक व भ्रामक प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके। फलत: भविष्य में नियामक मानदंडों को आसान बनाने पर सहमति बनानी जरूरी है। इसके लिये पूरी तरह से दरवाजे खोलना किसी आपदा को आमंत्रण जैसा भी हो सकता है। पेरिस में एक्शन समिट ऐसे वक्त में हुई है जब एआई में अमेरिकी वर्चस्व को चीनी कंपनी डीपसीक जबर्दस्त चुनौती दे चुकी है। उसने कम लागत में बेहतर एआई टूल पेश करके बताया है कि इस दौड़ में चीन कहीं आगे निकल चुका है। निस्संदेह, इस क्षेत्र में तमाम नई खोजों की संभावनाएं बरकरार हैं, लेकिन सुरक्षा मुद्दों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। निस्संदेह, आने वाला समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, लेकिन इसका अनियंत्रित विकास मानवता के लिए घातक भी साबित हो सकता है। ऐसे में एआई विकास में पारदर्शिता व नियमन के अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने भी जरूरी हैं। जरूरी है कि हम एआई की वैश्विक चुनौती के बीच अपने इंजीनियरों व वैज्ञानिकों की मेधा का बेहतर उपयोग करके नयी खोजों का मार्ग प्रशस्त करें। अन्यथा भारत एआई की नई खोजों की दौड़ में पिछड़ सकता है। फिक्र है कि भारत जैसे बड़ी बेरोजगारी वाले देश में कहीं एआई रोजगार संकट का वाहक न बने। कम जनसंख्या वाले विकसित देशों के लिये जहां यह तकनीक उपयोगी साबित होगी, वहीं श्रम प्रधान संस्कृति वाले भारत में यह विसंगति भी पैदा कर सकती है। निश्चित रूप से एआई के इस्तेमाल से बेहतर कार्य संस्कृति पैदा होगी, लेकिन यह प्रयास रोजगार के अवसर कम न करे। कृत्रिम मेधा के नियमन और नवाचार के साथ हम रोजगार के अवसर भी बढ़ाएं। भारत में एआई को तेजी से अपनाया जा रहा है। नीति आयोग ने भी इसे प्रोत्साहन देने के लिये राष्टीय नीति तैयार की है। आने वाले वर्षों में एआई की देश की सुरक्षा, आर्थिकी, चिकित्सा, कृषि तथा शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन जरूरी है कि युवाओं के लिये पर्याप्त रोजगार के अवसर भी सृजित हों। भारतीय युवा भी खुद को इस नई चुनौती के अनुरूप तैयार करें।

कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दलों में भी पतन का दौर

अजय कुमार

> राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, कि अरविंद केजरीवाल जिस तेजी से राजनीति में चमके थे उसी तत्परता से औंधे मुंह जा गिरे। अब उनका कोई भविष्य नहीं है और इसकी वजह है उनका बड़बोलापन और भरोसे की राजनीति न करना एवं उनकी अवसरवादिता। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का उभार और कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय दलों का पतन काफी कुछ कहता है। भले ही हार से बौखलाए मोदी और बीजेपी विरोधी नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हों? सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात करते हों? लेकिन ऐसा नहीं है कि विरोधियों को अपनी राजनैतिक कमजोरी और सियासी अपरिपक्वता का अहसास नहीं है, लेकिन बार-बार पराजित हो रहे यह नेता सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी को छोड़कर देश की किसी भी राजनैतिक दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है।

इसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सहित बहुजन समाज पार्टी,समाजवादी पार्टी,राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल,उद्धव ठाकरे की शिवसेना,शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों की लम्बी चौड़ी लिस्ट हैं। अब इसमें नया नाम कट्टर ईमानरदार 'आम आदमी पार्टी' का भी जुड़ गया है।

हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हार के लिये अभी तक ईवीएम मशीन या सरकारी मशीनरी पर किसी तरह की धांधली का आरोप नहीं लगाया है,जबकि उसी समय उत्तर प्रदेश में अयोध्या की चर्चित मिल्कीपुर विधान सभा सीट पर मिली जबर्दस्त हार के बाद समाजवादी पार्टी का प्रलाप लगातार जारी है। ऐसा ही प्रलाप कांग्रेस अध्यक्ष खरगे,नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सहित उनकी पार्टी के तमाम नेता भी करते रहते हैं। हालात यह है कि हार से बौखला कर मोदी विरोधी नेता उन्हें(मोदी) और बीजेपी को ही नहीं चुनाव आयोग,सीबीआई,ईडी जैसी एजेंसियों के खिलाफ भी भड़ास निकालते रहते हैं। यह नेता मोदी को नीचा दिखाने के लिये देश की छवि भी खराब करने से नहीं चूकते हैं। इसमें विदेश से पढ़ाई करके आने वाले टेक्नोटेक सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आईआरएस रह चुके अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे नेता शामिल हैं तो बिहार में लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव भी आरोप-प्रत्यारोप वाली सियासत से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी आभा को एकदम मटियामेट कर दिया है. जो केजरीवाल 12 साल पहले यूथ आइकॉन बनकर उभरे थे, वे अब धूल में लथपथ पड़े हैं। विधान सभा में 'दिल्ली का मालिक मैं हूँ' जैसे अहंकारी बयान देने वाले और हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाकर अपनी फजीहत करा चुके अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे आधे-अधूरे राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे थे मगर अब वे विधायकी भी गंवा बैठे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, कि अरविंद केजरीवाल जिस तेजी से राजनीति में चमके थे उसी तत्परता से औंधे मुंह जा गिरे। अब उनका कोई भविष्य नहीं है और इसकी वजह है उनका बड़बोलापन और भरोसे की राजनीति न करना एवं उनकी अवसरवादिता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से अधिक भद्द राहुल गांधी की पिटी है। पिछले कई चुनावों से दिल्ली में शून्य सीटों का रिकॉर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम दर्ज है।

अरविंद केजरीवाल की तरह ही नेताजी मुलायम सिंह यादव की राजनैतिक विरासत संभाले हुए अखिलेश यादव की है। 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपनी जगह अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था,जबकि अनुभव के नाम पर अखिलेश खाली हाथ थे। इसके बाद अखिलेश यादव अपने दम पर भले ही राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाये हों,लेकिन उनके बड़बोलेपन और अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की महारथ के चलते खूब नाम कमा रहे हैं।विवादित बयानबाजी की बात की जाये तो अखिलेश यादव अपने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का नया राजा कहकर प्रभु श्रीराम और उनके भक्तों का उपहास उड़ाने के चक्कर में खुद फजीहत करा बैठते हैं। उन्हें ट्रॉफी की तरह अपने साथ लेकर घूमते थे,लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश अपने होश खो बैठे हैं। सपा नेता हार से इतना बौखला गये हैं कि पार्टी के महासचिव प्रो रामगोपाल यादव तो यूपी के सरकारी अधिकारियों को ही नसीहत देने लगे हैं कि वह मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश सुनने की बजाये उन्हें नसीहत दें। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव हताशा में डूबते जा रहे हैं। रामगोपाल तो अयोध्या में रामलला के मंदिर को भी बेकार कह चुके हैं। सपा के तमाम नेता महाकुंभ में कथित अव्यवस्था को लेकर भी लगातार सीएम पर हमलावर हैं,लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को हासिल क्या हो रहा है,यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।क्योंकि समाजवादी पार्टी का पीडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मिल्कीपुर में तो सपा को यादवों तक का वोट नहीं मिला।

मोदी-शाह नए चेहरों को ही सीएम क्यों बनाते हैं?

बीजेपी मुख्यमंत्री के चुनाव में चलाया सामाजिक और जातीय समीकरण

नईदिल्ली।रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी एक रवायत कायम रखी। वो रवायत है- नए और कम चर्चित चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाना।बीजेपी आलाकमान ने पिछले 11 सालों में कम से कम 13 राज्यों में ऐसा किया। इसलिए पार्टी मोदी-शाह की लीडरशिप को कोई चुनौती नहीं देना चाहती। नए चेहरों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना और पुराने कद्दावर नेताओं को पीछे कर देना इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है।

पहली बार विधायक बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को चुना जाना आश्चर्य तो जगाता है लेकिन कई अन्य दावेदारों के बीच उन्हें चुने जाने के तीन मुख्य कारण हैं। पहली बात तो यह कि इस बार दिल्ली विधानसभा में प्रवेश करने वाले नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों में एक नहीं, कई दिग्गज थे। एक को दूसरे से ऊपर रखना भाजपा के लिए बहुत कठिन होता। रेखा गुप्ता को जाति के आधार पर दूसरों से ऊपर चुना गया।दूसरा, पिछले एक दशक के दौरान भाजपा ने कई राज्यों में सरकारें बनाई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ दो महिलाओं को ही चुना गया था, वह भी कुछ समय पहले। भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्रियों में से एक भी महिला नहीं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में एक महिला-चेहरा भाजपा के लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से जरूरी हो गया था। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी एक रवायत कायम रखी। वो रवायत है- नए और कम चर्चित चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाना।बीजेपी आलाकमान ने पिछले 11 सालों में कम से कम 13 राज्यों में ऐसा किया। इसलिए पार्टी मोदी-शाह की लीडरशिप को कोई चुनौती नहीं देना चाहती। नए चेहरों को मुख्यमंत्रीकी कुर्सी पर बैठाना और पुराने कद्दावर नेताओं को पीछे कर देना इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है।

अगर आप बीजेपी के नए मुख्यमंत्रियों की उम्र देंखेगे तो औसत 55 साल है। जैसे- मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, रेखा गुप्ता। ये सभी लीडर्स अगले 15-20 साल तक पार्टी को उस स्टेट में लीड कर सकते हैं, जिस तरह वसुंधरा, येदियुरप्पा और खुद पीएम मोदी ने किया। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में हर कार्यकर्ता अहम है। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं। किसी को कभी भी मौका मिल सकता है।मोदी से पहले पार्टी का कोर वोट बैंक ज्यादातर अपर कास्ट और बनिया माना जाता था। नई लीडरशिप से जातीय समीकरण भी साधा जा रहा है। 2009 में बीजेपी का ओबीसी वोट प्रतिशत 18.6% था, जो 2014 में बढ़कर 37.6% हो गया। 2019 में 44% और 2024 में लगभग बराबर था। वहीं, 2019 में बीजेपी को एससी-एसटी के 16.7% वोट मिले, जो 2024 में बढ़कर 20.8% हो गए। बीजेपी ने बड़े राज्यों में नए चेहरों के साथ उनकी जमीनी ताकत, अन्य विधायकों का समर्थन और मजबूत पकड़ भी देखी। इन राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी को आने वाले चुनावों में फायदा मिलने की उम्मीद है।

बीजेपी में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने का चलन कैसे शुरू हुआ?

2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहीं से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली।हरियाणा में बीजेपी ने राम बिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनकड़ और अनिल विज जैसे पुराने और चर्चित नेताओं की बजाय मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना कर बीजेपी ने चौंका दिया। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए गए। यहां से शुरू हुई रवायत एक-दो अपवाद छोड़कर लगातार जारी है और इसमें सबसे लेटेस्ट नाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जुड़ा है। वो पहली बार विधायक बनी हैं और सीधे मुख्यमंत्री बना दी गईं, जबकि होड़ में प्रवेश वर्मा जैसे चर्चित नेता भी थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और दिल्ली के बड़े जाट नेता हैं।

बीजेपी ने कहां-कहां नए चेहरों को सीएम बनाकर चौंकाया?

2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की हवा तेज थी। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा मनोज सिन्हा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन ऐन मौके पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान कर दिया गया। 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि शिवराज 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। सीएम के नाम का ऐलान होने से ठीक पहले की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें मोहन यादव पीछे कहीं बैठे दिख रहे थे। 2023 चुनाव के बाद यही पैटर्न राजस्थान में दिखा, जब वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता की जगह पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया। छत्तीसगढ़ में सीएम बने विष्णुदेव साय भी अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे थे। 2024 में हरियाणा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने अचानक मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया जबकि अनिल विज जैसे नेता कतार में थे।

3 ब्राह्मण... 2 वैश्य और 2 क्षत्रियों को सौंपी है कमान

27 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली है। पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। रेखा गुप्ता- वैश्य समुदाय से आती हैं, जो एक प्रमुख व्यापारी वर्ग है। बनिया समुदाय लंबे समय से बीजेपी का एक मजबूत और विश्वसनीय वोट बैंक रहा है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने से इस गठजोड़ को और मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जातियों पर

1. असम: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा असमिया ब्राह्मण जाति से आते हैं, विशेष रूप से सरमा समुदाय से। 10 मई 2021 को हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हिमंता से पहले सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम थे।

2. अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू मोनपा जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बसती है। मोनपा जनजाति अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है, जिसमें त्योहार, पारंपरिक नृत्य रूप और अनोखे अनुष्ठान शामिल हैं। 2016 में पेमा खांडू ने नबाम तुकी के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

3. छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हैं, जो कि कंवर समुदाय से आते हैं। ये अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल है। कंवर समुदाय मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है, खासकर सरगुजा संभाग में इस समुदाय के लोग बहुतायत में हैं।

4. गोवा: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सामंत मराठा राजनीति में एक प्रमुख राजनेता हैं, वह मराठा जाति से ताल्लुक रखते हैं। जो राज्य में एक प्रमुख समुदाय है।

5. गुजरात: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजराती कडवा पाटीदार समुदाय से आते हैं। पाटीदार गुजरात में एक प्रमुख जाति है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती है।

6. हरियाणा: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जो कि सैनी समुदाय से आते हैं, यह समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल है। सीएम नायब सिंह सैनी का परिवार मूल रूप से कुरुक्षेत्र के मंगोली जट्टन गांव से ताल्लुक रखता है, लेकिन वे कई साल पहले अंबाला जिले के मिर्जापुर में चले गए थे।

7. मध्य प्रदेश: देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जो कि यादव समुदाय से आते हैं। ये समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल है। मोहन यादव के परिवार की राजनीति और समाज सेवा में मजबूत पृष्ठभूमि है। उनके पिता पूनमचंद यादव अपने समुदाय के प्रमुख व्यक्ति थे और उनकी मां दिवंगत लीलाबाई यादव गृहिणी थीं।

8. महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं। फडणवीस के परिवार की राजनीति में मजबूत पृष्ठभूमि है। उनके पिता गंगाधरराव फडणवीस एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं।

9. राजस्थान: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो एक प्रमुख समुदाय है। भजनलाल शर्मा का परिवार एक साधारण पृष्ठभूमि वाला है। उनके पिता किशन स्वरूप शर्मा किसान थे, और उनकी मां गोमती देवी एक गृहिणी हैं।

10. त्रिपुरा: त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा वैश्य समुदाय से आते हैं। जो सामान्य वर्ग (जनरल केटेग्री) में शामिल है।

11. ओडिशा: ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल है। 6 जनवरी 1972 को ओडिशा के क्योंझर जिले के रायकला में जन्मे माझी का सूबे की राजनीति में प्रमुखता से उभरना संथाल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने 1997 में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की आदिवासी शाखा के सचिव का पद भी संभाला था।

12. उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि क्षत्रिय (ठाकुर) समुदाय से आते हैं। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर में जन्मे अजय सिंह बिष्ट (योगी आदित्यनाथ) का भारतीय राजनीति में कद उनकी मजबूत हिंदुत्व विचारधारा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेतृत्व के कारण बढ़ा है।

13. उत्तराखंड: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो कि कुमाऊंनी राजपूत (ठाकुर) जाति से ताल्लुक रखते हैं। धामी के परिवार की पृष्ठभूमि साधारण है। उनके पिता शेर सिंह धामी एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे, जो सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और उनकी मां विष्ण देवी एक गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पिथौरागढ़ में पूरी की और बाद में खटीमा के नागला तराई भाबर चले गए। धामी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की।

जातीय समीकरण का प्रभाव

बीजेपी की ओर से अलग-अलग जातीय समूहों को मुख्यमंत्री पद देने से यह साफ होता है कि पार्टी ने जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार की है। खासकर ओबीसी, एसटी और ब्राह्मण समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने विभिन्न सामाजिक समूहों को साधने का प्रयास किया है।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार

मोदी का जलवा....
राहुल फिर जीरो पर बोल्ड

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की बढ़त वापस छीनी; 5 राज्यों में कांग्रेस सिर्फ 23% सीटें जीत सकी

नईदिल्ली। जीरो- जीरो- जीरो! ये 2015, 2020 और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली सीटों की संख्या है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 52 से बढ़ाकर 99 पर पहुंची थी। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। मोमेंटम कांग्रेस के फेवर में दिख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये मोमेंटम वापस छीन लिया है। पिछले 8 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। यहां कुल सीटों की संख्या 624 है। इनमें कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें जीतीं। यानी जीत का स्ट्राइक रेट महज 23%। अगर ये एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड होता, तो उसमें लाल पेन से 'फेल' लिखा जाता। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को मिला मोमेंटम नरेंद्र मोदी ने वापस कैसे छीन लिया और क्या आने वाले बिहार, बंगाल चुनाव में कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी।

लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से मोमेंटम वापस कैसे छीना?

पेज-8 पर

एक दशक तक लगातार हार और संकटों से भरे रहने के बाद, 2024 का साल कांग्रेस और विपक्ष के लिए उतार-चढ़ाव भरा साबित हुआ। यह साल मुक्ति, उल्लास और फिर निराशा के क्षणों का साल था। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल किया, लेकिन इंडिया ब्लॉक को इस बात से राहत मिली कि बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत खो दिया।संख्या में इस गिरावट ने विपक्ष के लिए कुछ राजनीतिक गुंजाइश पैदा की। इससे इंडिया ब्लॉक को नई लोकसभा के शुरुआती सत्रों में मोदी 3.0 पर दबाव बनाए रखने में मदद मिली। हालांकि, उत्साह शांत होने से पहले ही, विपक्ष को दिल्ली,हरियाणा:और महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ा। यह मुख्य राज्य थे जिन्हें वे अपने लोकसभा चुनाव प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए जीतने की उम्मीद कर रहे थे।

2024 में कांग्रेस को मोमेंटम मिलने की सबसे बड़ी वजह
क्षेत्रीय दलों का साथ

दक्षिण के जिन राज्यों में 37 सीटें मिली हैं, वहां कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों से गठबंधन था। ऐसे ही उत्तरप्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से ही उसका खाता खुल सका है।दक्षिण के जिन राज्यों में उसका जहां क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं हुआ वहां उसे कोई सफलता नहीं मिली। ओडिशा इसका उदाहरण है।पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने समझ लिया था कि वो भाजपा को अपने दम पर नहीं हरा सकती। इसलिए इंडिया ब्लॉक बनाया गया। तमाम उठापटक के बावजूद जनता के बीच एकजुटता का पॉजिटिव मैसेज दिया। इससे सारे एंटी-बीजेपी वोट एकजुट हो गए।इसके अलावा कांग्रेस नैरेटिव बनाने में सफल रही। आरक्षण, संविधान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया। बीजेपी के 'अबकी बार, 400 पार' के नारे को ऐसे पेश किया कि अगर बीजेपी इतनी सीटें जीती, तो संविधान बदल देगी। जून 2024 में जब बीजेपी ने संसद में बहुमत खोया और सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथियों का सहारा लेना पड़ा, तो कांग्रेस ने इसे खुद के रिवाइवल मोमेंटम के तौर पर देखा।

हरियाणाः दो धड़े बंटे....
ओवर-कॉन्फिडेंस में हारी कांग्रेस

हरियाणा में कांग्रेस मोटे तौर पर 2 गुटों में बंटी थी- पहला गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरा एसआरके। एसआरके में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी हैं। गुटबाजी से नाराज किरण कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चली गईं।चुनाव की शुरुआत से ही दोनों खेमों के बीच की खींचतान साफ दिख रही थी। हुड्डा गुट ने 'हरियाणा मांगे हिसाब' अभियान शुरू किया, तो कुमारी सैलजा ने 'कांग्रेस संदेश यात्रा' का ऐलान किया।करीब 12 साल से यहां कांग्रेस का संगठन नहीं है। जून 2023 में राहुल गांधी के करीबी सिपहसालार दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने, लेकिन बाबरिया न तो संगठन बना पाए और न ही गुटबाजी रोक पाए। टिकट वितरण के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इलाज कराने चले गए।बताते हैं कि कांग्रेस जीत को लेकर इतना ओवर-कॉन्फिडेंट थी कि रिजल्ट से एक दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा के घर पर मीटिंग हुई, जहां वो नेताओं को मंत्रालय बांट रहे थे। जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 'अबकी बार 400 पार' के नारे की कीमत चुकानी पड़ी। वैसा ही हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस के नारे 'भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है' ने ऐसा माहौल बनाया, मानो चुनाव 'समाप्त' हो गया हो।

जम्मू-कश्मीरः लोकल मुद्दे गायब
नेशनल नेताओं की रैली का खास फायदा नहीं

कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ा। सीट-शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ, कांग्रेस को 32 सीटें मिलीं, लेकिन केवल 6 सीटें ही जीत पाई। इनमें से 4 मुस्लिम बहुल और 2 हिंदू बहुल सीटें हैं।राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में स्टेटहुड का दर्जा दिलाने की तो बात कही, लेकिन पानी, सड़क, बिजली, अन्य सुविधाओं जैसे लोकल मुद्दे नहीं उठाए। वे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते रहे।जम्मू-कश्मीर में पूरी लड़ाई 'नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेज बीजेपी' की थी। कांग्रेस केवल एक सहयोगी पार्टी बनकर रह गई थी।पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं,कांग्रेस को कश्मीर रीजन में जीत मिली, लेकिन जम्मू रीजन में उसके बड़े नेता हार गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। यहां लोकल मुद्दे चलते हैं। कांग्रेस लीडर्स ये बात समझ नहीं पाए।

महाराष्ट्रः नैरेटिव में पिछड़ी
अलायंस में खींचतान से नुकसान हुआ

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीतीं। यानी यहां कांग्रेस का मोमेंटम नजर आया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये ध्वस्त हो गया।जिस वक्त बीजेपी ने करीब 100 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी थी, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक नहीं तय हुआ था। दरअसल, कांग्रेस 110-120 सीटें मांग रही थी। वहीं उद्धव ठाकरे सीएम फेस बनना चाहते थे, लेकिन शरद पवार को ये नागवार था। यानी अलायंस के बीच खींचतान थी।शिवसेना (शिंदे) के सीनियर लीडर संजय राउत ने कहा, 'कांग्रेस का ओवर-कॉन्फिडेंस हरियाणा में उसकी हार के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस केवल उन क्षेत्रों में सहयोगियों पर निर्भर रहती है, जहां वह कमजोर है, लेकिन अपने मजबूत क्षेत्रों में उन्हें नजरअंदाज कर देती है।'चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस ने 'संविधान' को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में नहीं चला। कांग्रेस को समझना होगा कि एक मुद्दा एक ही चुनाव में चलता है।

झारखंडः कोई बड़ा नेता नहीं...
सब कुछ जेएमएम के सहारे

झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की कमान में इंडिया ब्लॉक ने चुनाव लड़ा। यहां कांग्रेस का कोई मजबूत और बड़ा नेता नहीं है। पूरे चुनाव की कमान जेएमएम के हाथों में रही। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरे प्रचार का जिम्मा उठाया। दोनों ने करीब 100-100 सभाएं कीं। झारखंड के सीनियर जर्नलिस्ट मानते हैं कि चुनाव जिताने में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना की मेहनत ज्यादा रही, कांग्रेस सिर्फ एक साइड किक बनकर रह गई।इंडिया ब्लॉक में जेएमएम को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को हेमंत सोरेन की बात माननी पड़ी। अगर कांग्रेस नहीं मानती तो उसे ही नुकसान उठाना पड़ता, जैसा हरियाणा में हुआ।

दिल्लीः कांग्रेस और आप आपस में भिड़े...
दोनों का खेल बिगड़ा

पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक, दिल्ली में कांग्रेस 5 से 10 सीटें चाहती थी, लेकिन 1 दिसंबर 2024 को केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वह कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। इससे कांग्रेस को झटका लगा और अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गए।उस वक्त कांग्रेस दिल्ली में आप के कुशासन के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही थी। कांग्रेस नेता अजय माकन केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जी कह चुके थे।जब राहुल ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए तो केजरीवाल ने पलटवार किया, राहुल गांधी ने मुझे खूब गालियां दीं, लेकिन मैं उनके बयानों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है, मेरी देश को। कांग्रेस ने कई सीटों पर आप के कद्दावर नेताओं के सामने अपने मजबूत नेता उतारे। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के मुकाबले संदीप दीक्षित, कालकाजी सीट पर आतिशी के खिलाफ अलका लांबा और वजीरपुर में,कके राजेश गुप्ता के सामने रागिनी नायक को उतारा। इन सब के बावजूद कांग्रेस को नाकामी हाथ लगी। एक भी सीट नहीं जीत पाई और 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई।

लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से मोमेंटम वापस कैसे छीना?

लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में चुनाव हुए। इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने बंपर जीत के साथ सरकार बनाई। बाकी 2 राज्यों में जबरदस्त टक्कर देते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इसके लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से अलग रणनीति अपनाई।

लोकसभा के बाद 5 राज्यों के चुनाव, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 23%

राज्य	कुल विधानसभा सीटें	कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे	कांग्रेस ने सीटें जीतीं	स्ट्राइक रेट
हरियाणा	90	89	37	42%
जम्मू-कश्मीर	95	38	6	16%
महाराष्ट्र	288	101	16	16%
झारखंड	81	30	16	53%
दिल्ली	70	70	0	0%
कुल	624	328	75	23%

Source: Election Commission of India

1. **लोकल और छोटी जातियों को साधा:** बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने के लिए बड़ी जातियों को छोड़ छोटी-छोटी जातियों पर फोकस किया। हरियाणा में बीजेपी ने 'जाट वर्सेज नॉन-जाट' फॉर्मूला अपनाया। वहीं महाराष्ट्र में मराठा के बजाय माली, धनगर, तेली, कुनबी, वंजारी जैसी छोटी जातियों को साधा।
2. **महिलाओं पर फोकस:** बीजेपी ने महिलाओं को एक वोटबैंक के तौर पर समझा। इसके लिए मध्यप्रदेश का उदाहरण सबसे सटीक है। मध्यप्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की। हरियाणा और दिल्ली में इसका वादा किया।
3. **आरएसएस का साथ मिला:** लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ के रिश्ते बिगड़ने की खबरें आईं। नतीजों में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद हरियाणा चुनाव में संघ जमीन पर उतरा और बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर हैट्रिक मारी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए संघ जमीन पर उतरा। दिल्ली में भी संघ ने करीब 50 हजार छोटी बैठकें कीं।
4. **मोदी के साथ लोकल लीडर्स भी उतरे:** करीब एक दशक से बीजेपी हर चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी।2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटजी में बदलाव करते हुए मोदी के साथ लोकल लीडर्स को भी आगे किया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, अनिल विज जैसे नेताओं ने चुनाव की कमान संभाली। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े जैसे नेताओं ने चुनाव का जिम्मा संभाला। ऐसे ही दिल्ली में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेताओं ने चुनाव को लीड किया।प्रधानमंत्री मोदी आज भी अपने दम पर बीजेपी के हर प्रत्याशी को वोट दिला देते हैं। बीजेपी संगठन की सोच से ज्यादा वोट उसे मिलते हैं। ये मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा है।

क्या कांग्रेस ने एक बड़ा मौका गंवा दिया, आगे की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?

लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की अगुआई कांग्रेस कर रही थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक की क्षेत्रीय पार्टियां अब सवाल उठाने लगी हैं कि कांग्रेस इस गठबंधन की अगुआई क्यों कर रही है, जबकि वह ग्राउंड पर वोट हासिल नहीं कर पा रही।हाल में हुए चुनावों में यह देखा गया कि बीजेपी का सामना क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं, जबकि कांग्रेस उनके सामने प्रमुख पार्टी थी। इससे क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक के खेमे में जो ऊर्जा आई थी, वह इस दिल्ली चुनाव के परिणामों के बाद कम हो जाएगी। विपक्ष के बिखरने का खतरा अब और बढ़ गया है।पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं, 'अभी कांग्रेस शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स कर रही है। उसके पास लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का कोई प्लान नहीं है। राहुल गांधी स्टेट लीडरशिप से दूर हो चुके हैं। प्रियंका वाड्रा भी कुछ खास नहीं कर रही हैं। साल के आखिर में होने वाले बिहार चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी के रहमोकरम पर रहने वाली है। कांग्रेस में जल्दी बदलाव नहीं हुए तो दिल्ली जैसे नतीजे आएंगे।'सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी की राय अलग है। वे कहते हैं,दिल्ली के नतीजों से कांग्रेस का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नेटवर्क देश के हर गांव तक है। अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत हो गया, तो स्थिति बदल सकती है।

अब सबसे आखिरी सवाल, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एसेट हैं या लायबिलिटी?

इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी मानते हैं कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव का सही तरीके से एनालिसिस करती तो उसे अपनी जमीनी हकीकत पता चल जाती। वे कहते हैं,लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने बूते कुछ हासिल नहीं किया। कांग्रेस को रीजनल पार्टियों की बदौलत ही 99 सीटें मिलीं।कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की जो गत हुई है उसके बाद इंडिया ब्लॉक का टूटना तय है। किसी भी परिवार में सबसे ज्यादा इज्जत उसी की होती है, जो कमाता है और परिवार को पालता है। ऐसा ही कुछ हाल इंडिया ब्लॉक का है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए राहुल गांधी एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी हैं।लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने समझ लिया था कि वो भाजपा को अपनी दम पर नहीं हरा सकती। इसलिए इंडिया ब्लॉक बनाया, लेकिन राहुल के काम करने के तरीकों से इंडिया ब्लॉक की रीजनल पार्टियां खुद को असहज महसूस कर रही हैं।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
28 फरवरी 2025

दिल्ली में अब रेखा राज

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को अनेक रेखाओं को पार करना होगा, उनके लिए क्या है सबसे बड़ी चुनौती ?

नईदिल्ली। छात्र नेता से पार्षद और पार्षद से विधायक बन कर दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता के सामने अनेक चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां भीतर बाहर दोनों जगह हैं, जिनसे उन्हें पार पाना होगा। उनकी पहली चुनौती उन उम्मीदों को पूरा करना और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, जो उनसे दिल्ली की जनता और खुद भाजपा ने पाली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उन सारी घोषणाओं और वादों को पूरा करना है, जो चुनाव के दौरान तीन किश्तों में जारी चुनाव घोषणा पत्र में किए थे और जिसे सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बार-बार दोहराया था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा था।

संकल्प पत्र में यमुना की सफाई स्वच्छ पेयजल साफ प्रदूषण रहित हवा दिल्ली को देना, प्रति वर्ष 50 हजार नई नौकरियों का सृजन महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देना मुफ्त बस यात्रा नालों गलियों सीवर की सफाई सड़कों की मरम्मत ट्रैफिक जाम से निजात समेत आप सरकार की मुफ्त बिजली पानी जैसी लोकलुभावन योजनाओं को जारी रखना शामिल होगा।

बतौर चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को अपनी पूर्ववर्ती शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी के कामकाज की रेखाओं को पार करके उनसे बड़ी लकीर खींचनी होगी। खासकर 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं और दिल्ली की सूरत बदलने वाली शीला दीक्षित के कामकाज से रेखा सरकार के कामकाज की तुलना होगी। इसके साथ ही रेखा गुप्ता को उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाते हुए भी ये संदेश भी देना होगा कि वो कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं हैं। इसके लिए उन्हें शीला और सुषमा का उदाहरण सामने रखना होगा। रेखा गुप्ता के सामने विपक्ष आम आदमी पार्टी के आक्रामक विरोध से निपटने की चुनौती होगी। 22 विधायक और 43 फीसदी मत प्रतिशत वाली आप विधानसभा के भीतर बाहर सरकार के विरोध में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि, शून्य विधायक महज साढ़े छह फीसदी वोट वाली कांग्रेस दिल्ली में खासी कमजोर है, लेकिन हमले वो भी करती रहेगी। इन बाहरी चुनौतियों के साथ ही पार्टी के भीतर वो नेता जिनकी नजर सीएम की कुर्सी पर थी, उनके भीतरघात से भी सजग रहने व निपटने की चुनौती होगी। हालांकि, मौजूदा भाजपा नेतृत्व के दौर में भीतरघात बहुत असरदार नहीं बचा है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा नेताओं की ही एक जमात उन्हें विफल होते भी देखना चाहेगी। मुख्यमंत्री को उन पर भी नजर रखनी होगी। आखिरी सबसे बड़ी चुनौती नौकरशाही पर सार्थक नियंत्रण और उसे जनोन्मुखी बनाने की होगी। साथ ही दिल्ली के सभी वर्गों समूहों और क्षेत्रों में संतुलन साधते हुए विकास करने की होगी। दिल्ली देश की राजधानी और केंद्र के सीधे नियंत्रण में है, इसलिए उनके हर काम पर देश की मीडिया की केंद्र की नजर रहेगी, इसलिए उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे।

एक तीर से भाजपा के कई निशाने

आखिर दिल्ली में भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा दे ही दिया और अचंभे की बात यह है कि इस बार भी भाजपा ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार देते हुए चौंकाया ही है। कहने वाले कहते हैं कि जिन नामों की भाजपा में चर्चा चलती है उनका नाम अपने आप ही कट जाता है। आलाकमान जो नाम तय करता है उसके ही भाग्य का ताला मुख्यमंत्री के पद के लिए खुलता है।

रेखा गुप्ता का नाम रवायत के अनुकूल

इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता का नाम चुना जाना उस लीक से हट कर है, क्योंकि इनका नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में काफ़ी ऊपर था और पिछले कई दिनों से तो कहा जाने लगा था कि वह ही भाजपा की दिल्ली में मुख्यमंत्री होंगी। हुआ भी वही। इसके कारण खोजें तो सब से बड़ा कारण तो यही है कि दिल्ली से एक महिला मुख्यमंत्री को हटाया जाना था तो उसकी जगह फिर महिला मुख्यमंत्री ही दिए जाने की संभावना बढ़ गई थी। हालांकि, नाम तो और भी महिला नेत्रियों के चल रहे थे फिर वही क्यों ? यह बात शुरू में ही तय हो गई थी कि किसी सांसद को यह ज़िम्मेदारी देकर एक सांसद की सीट पर फिर से चुनाव कराए जाने की संभावना बनाना ठीक नहीं है। एक शोर बिहार चुनाव के कारण किसी बिहारी या कम से कम पूर्वांचली के मुख्यमंत्री बनाए जाने का भी मचा था, लेकिन इस का संदेश शायद नीतीश कुमार तक गलत चला जाता। दूसरी ओर रेखा गुप्ता को मुख्य मंत्री बना कर वैश्य समाज में केजरीवाल की पकड़ को भी कमज़ोर करने का काम किया गया है।

वैश्यों को संदेश, संघ को खुश रखने की कवायद

हरियाणा में जन्मी और दिल्ली में पली बढ़ीं रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की उमीदवार वंदना कुमारी को 29 हज़ार से अधिक वोटों से मात दी थी। वह भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। समझा जाता है कि उनके नाम पर संघ ने पहले ही मुहर लगा दी थी। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई दिल्ली सीट जीतने वाले के मुख्यमंत्री बनने की धारणा को भी विराम मिला है। प्रवेश वर्मा हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री सीट के लिए प्रबल दावेदार थे लेकिन उनके समर्थकों ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद जिस तरह उनके नाम को आगे करने की कोशिश की शायद उस से उनको नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ही भाजपा के बड़े नेता हैं ऐसे में दिल्ली सरकार में किसी और बड़े नेता का उभरना शायद उचित नहीं रहता। वैसे, अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा का दावा मज़बूत हुआ था। इस लिए इस जाट नेता को किनारे लगाना बड़ा मुश्किल लगा होगा। इसलिए प्रवेश वर्मा को उप-मुख्य मंत्री बनाना पड़ा है जिससे दिल्ली और दिल्ली से लगते राज्यों में जाट बहुल क्षेत्रों में कोई ग़लत संदेश न चला जाए।

दिल्ली कैबिनेट की पहली मीटिंग में अहम फैसलों पर लगी मुहर, आयुष्मान योजना को मंजूरी मिली

दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में दो अहम फैसले हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली की विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बैठक में हमने दो मुख्यता एजेंडे पर बात किया और उसे पास किया। पहला- दिल्ली में आयुष्मान योजना को हमने सर्वसम्मति से पारित किया है। दिल्ली में 5 लाख का टॉपअप दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार देगी। जो कि जल्द ही लागू किया जाएगा। दूसरा- 14 सीएजी रिपोर्ट पेंडिंग है पहले हाउस में उन रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हमने जो जनता से वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे। हमने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कर दिया है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के भाजपा के दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये देने के वादे को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा, यह हमारी सरकार है तो एजेंडा हमारा होगा। तो हमें काम करने दीजिए।

नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की आंधी में उड़ा पंजा

10 नगर निगम, 35 नगर पालिका और 81 नगर पंचायत पर भाजपा का कब्जा

रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे के कुल 173 निकायों में से बीजेपी ने एकतरफा प्रदर्शन किया। सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी के प्रत्याशी जीते, यहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इनमें सबसे बड़ी जीत रायपुर से मीनल चौबे और सबसे छोटी जीत चिरमिरी से रामनरेश राय की हुई है। मीनल चौबे 1 लाख 53 हजार से ज्यादा मतों से दीप्ति दुबे को हराया है, जबकि रामनरेश राय ने डॉ. विनय जायसवाल को 5 हजार से ज्यादा वोटों से मात दी है। इसके अलावा 49 में से 35 नगरपालिकाएं भाजपा के खाते में गईं, जबकि सिर्फ 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। आप ने बिलासपुर की बोदरी नगर पालिका में जीत दर्ज की। निकाय चुनाव में 'आप' की यह पहली जीत है। 11 फरवरी को 114 नगर पंचायत में भी वोटिंग हुई थी। इसमें भी बीजेपी ने 81 पंचायत पर कब्जा जमाया। यानी 173 निकायों में 126 पर बीजेपी और महज 30 पर ही कांग्रेस जीत सकी है।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त देने के बाद नगर निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने सूपड़ा साफ करते हुए महापौर के सभी 10 पदों पर जीत हासिल की। सत्ताधारी दल भाजपा ने सभी 10 नगर निगमों में महापौर पद तथा 35 नगर पालिका परिषदों और 81 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है।आठ नगर पालिका परिषदों और 22 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर विपक्षी दल कांग्रेस ने जीत दर्ज की जबकि आम आदमी पार्टी (आप) ने एक नगर पालिका परिषद और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने एक नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है।पांच नगर पालिका परिषदों और 10 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना कब्जा जमाया।

नगर निकाय चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। साय ने संवाददाताओं से कहा, ''आज का दिन भाजपा और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ऐतिहासिक है। यह छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा क्योंकि भाजपा ने नगर निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।''उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता और मतदाताओं ने भाजपा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री की गारंटी और राज्य सरकार के विकास कार्यों में विश्वास जताया है, जिसके लिए वह उनका आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ''कांग्रेस वादे तो करती है लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं करती, लेकिन भाजपा अपने वादे पूरे करेगी।''

निकाय-चुनाव में बीजेपी की जीत की 5 बड़ी वजह

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को एकतरफा जीत मिली है। 10 नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 49 नगर पालिकाओं में 35 में बीजेपी, 8 में कांग्रेस, 1 में आम आदमी पार्टी 5 में निर्दलीयों को जीत मिली। इसके अलावा 114 नगर पंचायत में 81 में भारतीय जनता पार्टी, 22 में कांग्रेस 1 में बसपा और 10 पर निर्दलीयों को जनता ने चुना है। इस जीत की 5 बड़ी वजह रहीं। इनमें 6 से 7 महीने पहले से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और अन्य मंत्री विधायक जुटे थे।14 महीने की भाजपा सरकार ने 7400 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। इसका निकाय चुनाव में बड़ा असर देखने को मिला। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल मजबूती से निकाय चुनाव लड़ते दिखाई नहीं दिए। कुछ अन्य फैक्टर भी रहे, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ी जीत मिली।

1. हर जिले में लोकार्पण कार्यक्रम

रायपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा तक हर जिले में लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, पानी की टंकी, स्कूल-हेल्थ सेंटर के लिए बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया।इसके जरिए भाजपा यह बताने की का प्रयास करती रही कि कांग्रेस के दौर में कोई काम नहीं हुआ अब आगे काम होगा, इसका असर वोटर्स पर पड़ा। इलाके के जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री अरुण साव मंचों पर दिखाई देते थे।

2. कन्फ्यूज नजर आया विपक्ष

नवंबर 2024 आते-आते छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनती रही। कभी दिसंबर, कभी जनवरी तो कभी फरवरी में चुनाव होने की बातें सामने आती रहीं। कांग्रेस यह कहती रही कि कि सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुकी थी।संगठन में 20 से ज्यादा समितियां बनाकर प्रदेशभर में प्रत्याशी चयन, घोषणा पत्र तैयार करने का काम हो रहा था। तब तक कांग्रेस ऐसी तैयारी में नहीं थी। कांग्रेस के भीतरी हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले वाली रात तक प्रत्याशी तय कर पाए। चुनावी अभियान में विपक्ष कन्फ्यूज और बैकफुट पर ही नजर आया। घोषणा पत्र आरोप पत्र लाकर कांग्रेस ने जनता को साधने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा, लोकसभा और अब नगरीय निकायों में भी कामयाबी नहीं मिली। घोषणा पत्र आरोप पत्र लाकर कांग्रेस ने जनता को साधने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा, लोकसभा और अब नगरीय निकायों में भी कामयाबी नहीं मिली।

3. घोषणाओं का वोटर्स पर असर

कांग्रेस से पहले भाजपा अपना घोषणा पत्र लेकर आई। जिलों की लोकल समस्याओं के हिसाब से भी अलग घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी होने पर टैक्स में छूट देने, पट्टा मालिकों को जमीन का मालिक बनाने जैसी बातों का शहरी और ग्रामीण इलाकों में असर दिखा।भाजपा विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा से महतारी वंदन योजना को भुनाती दिखी। महिलाओं के बीच यह बात पहुंचाई गई कि जिन महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है, उन्हें भी निकाय चुनाव के बाद मिलेगा। कई जगहों पर आचार संहिता के दौरान फॉर्म भरवाने के मामले भी सामने आए। पट्टे पर रहने वालों से भी मालिकाना हक दिलाने का फॉर्म रवाया जाता रहा। इसका वोटर्स पर साइकोलॉजिकल असर पड़ा।

4. माहौल बनाने में बीजेपी आक्रामक

रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के लिए नामांकन रैली निकाली। ऐसा कोई आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं हुआ। कांग्रेस महापौर पद की प्रत्याशी दीप्ति दुबे स्कूटी पर नामांकन दाखिल करने गईं। सादगी के लिहाज से ये चर्चा में जरूर रहा, लेकिन माहौल बीजेपी के पक्ष में रहा। रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने रोड शो भी किया। यह स्थिति लगभग प्रदेशभर में रही। आक्रामकता से भीड़ जुटाकर बीजेपी लगातार सभा और रोड शो करती दिखी। कांग्रेस इस मामले में काफी पीछे रही।

5. कांग्रेस ने झेली एंटी इनकंबेंसी

रायपुर समेत प्रदेश के अन्य नगर निगमों में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है। कांग्रेस का काम बागियों ने भी खूब बिगाड़ा। पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने के अलावा कई कांग्रेसी नेता ऐसे भी रहे, जिन्होंने ठीक से नामांकन दाखिल नहीं किया।उनके नामांकन रिजेक्ट हो गए। जैसे धमतरी महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से रद्द हो गया।कोंडागांव में वोटिंग से 2 दिन पहले सुभाष चंद्र वार्ड की कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा भाजपा में शामिल हो गई।इसी तरह का माहौल प्रदेशभर में रहा। रायपुर में मेयर इन काउंसिल में शामिल रहे कांग्रेस नेता बंटी होरा, जितेंद्र अग्रवाल, आकाश तिवारी ने कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ा। कांग्रेस को इस बार एंटी इनकंबेंसी भी झेलनी पड़ी।एंटी इनकंबेंसी के चलते इस बार बीजेपी को मतदाताओं ने सपोर्ट दिया। उदाहरण के तौर पर रायपुर में 15 साल से कांग्रेस का महापौर रहा। भाजपा को लगातार महापौर चुनाव में हार मिली थी। हालांकि यह भी ट्रेंड रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार होती है, निकायों में उसे ही कामयाबी मिलती है।

तेजस्वी के लिए मुसीबत बने लालू!

'भूरा बाल' से 'फालतू कुंभ' तक... तेजस्वी को लालू यादव के किन बयानों से जूझना होगा, पिता की बदौलत यहाँ तक आये, आगे नुकसान या फायदा?

बिहार में इस साल चुनाव होना है। समीकरण लोकसभा चुनाव की तरह ही हैं, लेकिन बिहार चुनाव में मुकाबला नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव होगा। लालू भी तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन, लगता है कि तेजस्वी की मुसीबत भी वही हैं।

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के भूतपूर्व रेल मंत्री और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जून में 77 साल के हो जाएंगे। माना जाता है कि वह जब तक रहेंगे, बिहार की राजनीति में धुरी बनकर रहेंगे। वह अपने बड़े बेटे को मंत्री और छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं। एक बार नहीं, दो-दो बार। अब छोटे बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने की बात कह रहे हैं। लेकिन, वह बीच-बीच में बेटे के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दे रहे हैं। जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आसपास राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टरों से कुछ समय के लिए लालू यादव गायब हुए थे, कहीं वही हालत पांच साल बाद करना तेजस्वी यादव की मजबूरी न बन जाए। परिस्थितियां तो यही इशारा कर रहीं।बिहार में इस साल चुनाव होना है। समीकरण लोकसभा चुनाव की तरह ही हैं, लेकिन बिहार चुनाव में मुकाबला नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव होगा। लालू भी तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन, लगता है कि तेजस्वी की मुसीबत भी वही हैं।

भूरा बाल साफ करो... के कारण तेजस्वी के पैर अब भी बंध रहे

तेजस्वी यादव नई तरह की राजनीति कर रहे। उन्हें पता है कि उनकी जाति, यानी यादवों का वोट ज्यादातर उनके साथ है और आगे भी इसमें बहुत बिखराव लाने वाला सामने से कोई 'योद्धा' नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का डर कायम रहने के कारण ज्यादातर मुसलमान अब भी उनके वोटर हैं। यानी, पिता लालू यादव का बनाया माई (मुसलमान-यादव) समीकरण उनके काम आता रहेगा। लेकिन, लालू का ही दिया नारा 'भूरा बाल (भूमिहार-राजपूत-ब्राह्मण-लाला) साफ करो' उनकी राह में अब भी रोड़ा बना हुआ है। दिवंगत सुशील मोदी जबतक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, वोटरों को लालू का यह नारा याद दिलाते रहे। चुनाव आ रहा है तो लालू के पुराने नारों पर भाजपा-जदयू का काम चल रहा है। उस समय का वीडियो नहीं, लेकिन खबरें खोजकर वायरल करने की तैयारी है। वैसे, तेजस्वी भी जानते हैं कि इस नारे के कारण ही उनके पैर कई बार बंध जा रहे हैं।

कुंभ फालतू है... के पहले भी लालू लगातार कुछ-न-कुछ बोल चुके

लालू यादव पत्नी राबड़ी देवी और बेटों के साथ बीच-बीच में मंदिरों की परिक्रमा भी कर चुके हैं, लेकिन उनके सनातन विरोधी बयानों के कारण तेजस्वी के लिए बार-बार मुसीबत सामने आ जा रही है। तेजस्वी यादव सबकुछ सोचकर बोल रहे, जबकि लालू हमेशा विवादित बयान दे ही दे रहे। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और उससे पहले प्रयागराज में ऐसी ही घटना को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव ने बाकी बातों के साथ यह भी कह दिया कि 'फालतू है कुंभ'। इसपर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। चुनावी साल में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड ने भी इसे लेकर लालू को घेर रखा है। इससे पहले लालू ने मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू होने के पहले 'आंख सेंकने जा रहे हैं' बोलकर महिलाओं के बीच इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि उसे ठंडाने के लिए तेजस्वी को घोषणा पत्र से पहले ही 'माई बहिन मान योजना' का पटाक्षेप करना पड़ा।

लालू के इन बयानों को भाजपा बनाने वाली है मुद्दा

- **अयोध्या श्रीराम मंदिर की रथ यात्रा रोकने के लिए चर्चित रहे लालू ने पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा से पहले कहा था- 'बाबरी-विध्वंस के लिए आडवाणी-मोदी सब जिम्मेदार हैं।'**
(एक साल के अंदर अयोध्या का श्रीराम मंदिर सनातन आस्था का प्रतीक हो गया है। राम मंदिर के खिलाफ बोलना रथ रोकने से ज्यादा बड़ा ध्रुवीकरण करा सकता है।
- **पिछले साल मई में लालू प्रसाद ने धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा था- मुसलमानों को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए।**
(धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर लालू ने अपने ऊपर शुरू से लग रहे तुष्टीकरण के आरोपों को एक तरह से सही करार दिया, हालांकि बाद में उन्होंने पैर खींचे भी थे।
- **पिछले साल दिसंबर में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की यात्रा में महिला संवाद की बात पर कहा था- वह तो आंख सेंकने के लिए जा रहे हैं।**
(महिलाओं ने राज्य स्तर पर इसपर जमकर हंगामा किया था। भाजपा-जदयू ने इसे पहले तत्काल मुद्दा बनाया। माई बहिन मान योजना लोकर तेजस्वी घाव भरने की कोशिश कर चुके हैं।
- **इस साल भी जनवरी तक लालू प्रसाद तेजस्वी से उलट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कह रहे थे- अभी भी चुनाव में समय है, वापस आने पर स्वागत है।**
(तेजस्वी यादव जनता के बीच नीतीश कुमार को थके हुए बताकर अब उनमें उम्मीद नहीं जता रहे। ऐसे में राजद के अंदर दो फाड़ की बात भाजपा-जदयू लगातार उठा रही हैं।

तेजस्वी के पास मुद्दों की भरमार

विपक्ष के पास मुद्दों की कभी कमी नहीं होती। उसे जरूरत होती है कुशल रणनीति से मुद्दों को भुनाने की। 1990 से लगातार 15 साल तक सत्ता में रहे लालू-राबड़ी को उखाड़ फेंकने में नीतीश कुमार को अगर कामयाबी मिली तो उसके दो-तीन मुद्दे ही प्रमुख थे। अच्छी रणनीति बना कर नीतीश ने उन्हें भुना लिया। कामयाबी के लिए यही काम आरजेडी को करना होगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश शासन में अपराध और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना कर एनडीए के सामने मुसीबत खड़ी करने का प्रयास तो शुरू किया है। वे बार-बार कह रहे हैं कि बिहार में कोई भी काम बिना 'डीके टैक्स' चुकाए नहीं होता। नीतीश की सेहत और उम्र को आधार बना कर तेजस्वी उन्हें लाचार सीएम बताते रहे हैं।

बिहार में सत्ता के लिए बेचैनी

बिहार की सत्ता के लिए आरजेडी में बेचैनी है तो एनडीए भी सत्ता हाथ से न जाने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में एनडीए इस बार रिकार्ड तोड़ने के लक्ष्य साथ चल रहा है। महागठबंधन भी सरकार बनाने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिल रही सफलता से एनडीए का उत्साहित होना स्वाभाविक है। इधर महागठबंधन का मानना है कि दूसरे राज्यों से बिहार का मिजाज अलग है। इसलिए एनडीए की दाल बिहार में नहीं गलने वाली। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यही कहा है। वे कहते हैं कि हम लोगों के रहते भाजपा का सपना बिहार में साकार नहीं होगा। तेजस्वी यादव उनसे एक कदम आगे बढ़ कर जिस तरह की लोकलुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलने का पक्का भरोसा है।

नीतीश पर भी लालू की बात फिट

यह सर्वविदित है कि लालू यादव और नीतीश कुमार समाजवादी कुल-गोत्र के हैं। तीन साल पहले नीतीश कुमार भी भाजपा के कट्टर विरोधी बन गए थे। वे घोषित तौर पर कहते थे कि मर जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा के विरोध के लिए ही नीतीश ने विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' की नीव रखी थी। इसके बावजूद वे बाद में भाजपा के साथ आ गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह एकनाथ शिंदे की जगह भाजपा ने अपना सीएम बना दिया, उससे नीतीश कुमार पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। इस आशंका को अमित शाह के उस बयान ने हवा दे दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में अगले सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। उसके बाद भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता भी गारंटी के साथ नहीं कहते कि अगली बार एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। माना जा रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए ही लालू ने नीतीश को अपने बयान से उकसाने की कोशिश की है।

81.99 प्रतिशत आबादी हिंदुओं की, इसका ध्रुवीकरण रोकना तेजस्वी के लिए चुनौती

बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण का दायरा बदला था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण सब अटका हुआ है। उस रिपोर्ट का इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल उपयोग करेंगे। उसी रिपोर्ट के हिसाब से जातीय आधार पर कमोबेश सीटें बंटेंगी। उस रिपोर्ट ने यह तो साफ कर दिया था कि बिहार में सबसे ज्यादा संख्या यादव जाति के लोगों की है और सामान्य जातियों को मिलाकर जितनी संख्या होती है, उससे कुछ ही कम हैं यादव। ऐसे में तेजस्वी अपनी जाति के साथ नजर आएंगे, इससे भी इनकार नहीं। यह तो वैसे भी लालू प्रसाद का फॉर्मूला है। लेकिन, हिंदू धर्म की बाकी जातियों के साथ यादवों के अंदर भी कट्टर सनातन की जो बातें हैं, वह लालू के बयानों के कारण तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। मतलब, कुंभ फालतू है... वाली बात निकली है तो दूर तक जा सकती है। भाजपा इसकी तैयारी में है भी, क्योंकि जातीय जनगणना की रिपोर्ट भी कह चुकी है कि बिहार में 81.99 प्रतिशत यानी लगभग 82% हिंदू हैं। इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या 17.7% है। शेष ईसाई सिख बौद्ध जैन या अन्य धर्म मानने वालों की संख्या 1% से भी कम है।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
28 फरवरी 2025

अकल चबूतरे से

डुबकी में छिपी संभावनाएं तलाशने का दौर

व्यंग्य

डॉ. हेमंत कुमार पारीक

महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ देख मन मचल रहा है। भीड़ में शामिल हो हम भी जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, पक्के सनातनी हैं। कुछ न बन सके तो कम से कम भीड़ में तो बने रहें। मौका है और दस्तूर भी चौका लगाने का। सुन रहे हैं कि इस वक्त फिल्मों में अपना करिअर बनाने उतरी हीरोइनें भी डुबकी लगा दीक्षा लेने की तैयारी कर रही हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब एक भूली-बिसरी अभिनेत्री अचानक अखाड़े की बड़ी कुर्सी की खलीफा हो गयी।सुनते ही हमारे घर काम करने वाली बाई रामप्यारी की सांस फूलने लगी। लोग मानें न मानें पर वह तो अपने आपको हीरोइन से कम न समझती। उतावली हो गयी डुबकी लगाने के लिए। बर्तनों को पटकना शुरू कर दिया उसने। झाड़ू की सींकें तोड़ने लगी।देख लो दिल्ली में क्या हुआ तार-तार हो गयी झाड़ू। कभी भाई साहब कंधे पर उठाए-उठाए घूमा करते थे। हमेशा दूसरों को झाड़ने की फिराक में रहते थे। अब देखो झाड़ू उल्टी पड़ गयी। सो भाई झाड़ू का अपमान अच्छा नहीं होता।हमें तो लगा था कि अबकी बार झाड़ू के साथ पोंछा भी लेकर आएंगे। पर उनके हाथ में वेक्यूम क्लीनर देख हम चकरा गए। कारण पूछा तो हंसते हुए बोले, शीशमहल में झाड़ू नहीं चलती। तौहीन होती है शीशमहल की। जब तक कुर्सी पर न थे खूब खेले झाड़ू से और कुर्सी पर आते ही उसे दुत्कार दिया, तू कौन खामखां और फिर सबने देखा, खेला हो गया। अब मिर्जा साहिब का शे'र उन पर खूब फिट होता है- उम्रभर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।खैर, कामवाली बाई जोश में है इस वक्त। बर्तनों की पटका-पटकी जारी है। इस असार संसार में अपने आपको सनातनी सिद्ध करना चाहती है। हमने कहा, ऐसा न करो रामप्यारी! जोश में होश न खोओ। वे सब तो भरीपूरी हैं। दीक्षा ले भी लें तो भी वापसी का टिकट उनके पर्स में रहता है। मगर अगर तूने दीक्षा ली तो फिर वापस नहीं लौटने वाली। कहीं भिक्षा पात्र ले वहीं कहीं सड़क या चौराहे पर न बैठना पड़े। नकल में शक्ल बिगड़ जाती है।फिलवक्त तो वसंत और वेलेंटाइन का मौसम है। होली आ रही है। अपने परिवार के संग वेलेंटाइन-डे मना। मन चंगा रख, बनी-ठनी रहेगी।ज्यादा ही फड़फड़ा रही है तो दो-चार और घर तलाश ले। रामप्यारी से रेखा या राखी बनने की कोशिश न कर। फिर भी समझ नहीं आता तो जा रामप्यारी तू भी लगा ले एक डुबकी।

मोदी के मन में है मोहन

भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की प्रशंसा की और इस बेहतर आयोजन के लिए उनकी पीठ थपथपाई... जायज है इससे मुख्यमंत्री के नंबर तो बढ़े ही मगर यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह दो दिन का समय मध्य प्रदेश को दिया..उससे ये भी साबित होता है कि मोदी जी मोहन कार्यकाल की अब तक की उपलब्धियों से संतुष्ट है और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद से भी इसकी पुष्टि होती है..मोदी जी ने अपनी मौजूदगी से न सिर्फ समिट को सफल बनाया बल्कि निवेश के रास्तों को भी आसान कर दिया...

अब समिट में शामिल देश- विदेश के दिग्गज उद्योगपति / निवेशक बढ़-चढ़कर घोषणाएं करेंगे...प्रधानमंत्री ने भी उनसे यही अनुरोध किया कि यही सही वक्त है जब वे मध्य प्रदेश में निवेश कर सकते हैं... मोदी जी ने उज्जैन के महाकाल लोक की भी तारीफ की और भोपाल पहुंचे उद्यमियों से अनुरोध किया कि वे महाकाल लोक देखने के साथ बाबा महाकाल का भी आशीर्वाद प्राप्त करें... इसमें कोई शक नहीं की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पहले रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित कर पूरे प्रदेश में माहौल बनाया और स्थानीय उद्यमियों और निवेशकों को भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार सही मायने में उद्योग मित्र की भूमिका निभाएगी ...2025 को जिस तरह मुख्यमंत्री ने उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया, उसकी भी सराहना मोदी जी कर गए.. यानी कुल मिलाकर मोदी के मन में मोहन है और वह उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री की टॉप पोजीशन में आ गए हैं... दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी इन्वेस्टर समिट के विराट आयोजन से साबित कर दिया कि वह भी किसी से कम नहीं है और राजनीति के साथ सभी फील्ड के माहिर खिलाड़ी है... ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि समिट का शुभारंभ जहां मोदी जी ने किया, वही समापन में अमित शाह जी मौजूद रहे...ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तो शुरुआत है.. मप्र ने देश के सबसे विकसित राज्य बनने की अपनी फर्राटा दौड़ का ट्रेलर दिखा दिया है...बाबा महांकाल के भक्त मुख्यमंत्री इस में अवश्य सफल साबित होंगे.. !

कुर्सी को लेकर नाराज हो गए शिवराज मामा, सुना दी व्यथा

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर कुर्सी को लेकर नाराज हां गए है। इस बार शिवराज सिंह राजनीतिक कुर्सी नहीं बल्कि हवाई सेवा देने वाली एयर इंडिया विमान की टूटी कुर्सी पर नाराज हो गए है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एयर इंडिया को फटकार लगाते हुए एक पोस्ट की है।शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक एआई 1436 में टिकिट करवाया था, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। शिवराज सिंह ने आगे लिखा कि जब मैंने विमानकर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की? उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदल कर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं, मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। शिवराज सिंह ने यात्रियों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए आगे लिखा कि मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा।

अमित शाह की विजयवर्गीय से सीक्रेट मीटिंग

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह जब समिट का समापन कर भोपाल से कोयंबटूर के लिए रवाना होने स्टेट हैंगर पहुंचे तो उन्होंने नेताओं से मंत्री विजयवर्गीय के बारे में पूछा। हालांकि उस समय विजयवर्गीय इंदौर के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन शाह के फोन पर वे तुरंत वापस भोपाल लौटे और स्टेट हैंगर पर शाह से मिले। बीजेपी सूत्रों के अनुसार स्टेट हैंगर पर केन्द्रीय मंत्री शाह ने एयरपोर्ट के लाउंज में चुनिंदा नेताओं के साथ एक सीक्रेट शॉट मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम मोहन, वीडी शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। शाह जब लाउंज के लिए जा रहे थे उस दौरान उन्होंने विजयवर्गीय से कानाफूसी भी की, हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं हुआ। वही मीटिंग में भी नेताओं के साथ क्या गुफ्तगू हुई यह भी स्पष्ट नहीं है। शाह और विजयवर्गीय की इस सीक्रेट शॉट मीटिंग को लेकर कई मायने निकाले जाने लगे है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अमित शाह नए प्रदेशाध्यक्ष के नाम की पर्ची दिल्ली ले गए हैं।

छाया मिले आपकी, सिर पर आपका हमेशा हाथ हो,
जीवन के हर मोड़ पर, सदा आपका आशीर्वाद हो...

भावपूर्ण श्रद्धांजलि

मालव समाचार के संस्थापक और हमारे प्रणेता

स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

की 38वीं पुण्यतिथि पर हम सब श्रद्धानवत हैं... दिवंगत पुण्यात्मा के चरणों में शत्-शत् नमन् श्रद्धा व आदर के सुमन समर्पित करते हैं...

जन्म
9 अप्रैल 1929

महाप्रयाण
28 फरवरी 1987

विनीत: मालव समाचार परिवार

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद खुजनेरी द्वारा अपना देश प्रिंटर्स से अनुबंध पर 204 शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इंदौर 452001 से मुद्रित तथा प्रकाशित।
संपादक: विनोद खुजनेरी। मोबाइल: 98270-10709। आरएनआई पंजीयन क्रमांक 13186/67